भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 3216

04 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना

3216. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा क्या है और शेष कार्य कब तक पूरा किया जाएगा;

(ख) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान सरकारी मंत्रालयों/कार्यालयों पर किराया व्यय के रूप में किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को पूरा करने के बाद कितनी राशि की बचत होगी?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) आज की तारीख तक सेंट्रल विस्टा विकास/पुनर्विकास मास्टर प्लान के अंतर्गत 5 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है | ब्यौरा निम्नवत है:

परियोजना का नाम	वास्तविक प्रगति	पूरा करने की लक्षित तिथि
नया संसद भवन	70%	नवम्बर, 2022
सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास	कार्य लगभग पूरा हो चुका है	
कॉमन केन्द्रीय सचिवालय भवन 1, 2 और 3	17%	दिसम्बर, 2023
उप राष्ट्रपति एन्क्लेव	24%	जनवरी, 2023
एक्जिक्यूटिव एन्क्लेव	कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है		

(ख) और (ग): संपदा निदेशालय सामान्य पूल कार्यालय आवास (जीपीओए) भवनों में मंत्रालयों/विभागों को कार्यालय हेतु स्थान प्रदान करता है | संपदा निदेशालय सामान्य पूल कार्यालय आवास (जीपीओए) भवनों में कार्यालय स्थान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मांग करने वाले मंत्रालयों/विभागों को 'गैर-उपलब्धता प्रमाणपत्र' (एनएसी) जारी करता है, ताकि वे स्थानीय निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी मालिकों आदि से कार्यालय स्थान किराए पर ले सकें | संपदा निदेशालय ने वर्ष 2021-22 में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को 11.98 लाख वर्ग फुट स्थान के लिए गैर-उपलब्धता प्रमाणपत्र जारी किया है और 69 विभागों ने सूचित किया है कि वे अपने कार्यालय स्थान के लिए 1,177.25 करोड़ रूपये सालाना किराए का भुगतान कर रहे हैं |